आज़ादी का अमृत महोत्सव

सहकार से समृद्धि

प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं और नए पहलुओं के बारे में जागरूकता

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT)

National Council For Cooperative Training

(An Autonomous Society Promoted by Ministry of Cooperation, Government of India)

List of Articles/Editorials on Computerization of PACS

Index Page

State	Language	Newspaper	Edition	Date of Publication	Contributor	Index Page No.
New Delhi	Hindi	यूनीवार्ता भारत की अग्रणी संवाद समिति	**All India** http://www.univarta.com/	09/01/2023	श्री मनोहर, उप्रेती वार्ता	1.
छत्तीसगढ़	हिन्दी	दैनिक श्रमबिन्दु	रायपुर	10/01/2023	श्री लखन लाल साहू	2.
Punjab	Punjabi	Rozana Spokesman	Chandigarh	12/01/2023	RICM, Chandigarh	3.
Chhattisgarh	Hindi	Samvet Srijan	Raipur https://samvetsrijan.com/01/12/national/79342/	12/01/2023	Shri Ravi Bhoi, Editor	4.
Chandigarh	Hindi	दैनिक जागरण	चंडीगढ़	13/01/2023	RICM, Chandigarh	5.
Punjab	Punjabi	Punjabi Jagran (Chandigarh)	Chandigarh	13/01/2023	RICM, Chandigarh	6.
Punjab	Punjabi	Punjabi Tribune	Chandigarh	16/01/2023	RICM, Chandigarh	7.
चंडीगढ़	Hindi	दैनिक जागरण	चंडीगढ़	17/01/2023	RICM, Chandigarh	8.
Manipur	Manipuri	Hueiyen Lanpao	Manipur	18/01/2023	ICM, Imphal	9.

Manipur	Manipuri	Ichel Express	Manipur	18/01/2023	ICM, Imphal	10.
Manipur	English	The Tamenglong Times	Manipur	18/01/2023	ICM, Imphal	11.
चंडीगढ़	हिन्दी	रैस्टवे एक्स्प्रेस	चंडीगढ़	18/01/2023	RICM, Chandigarh	12.
Manipur	English	NISIN Thuhiltu	Imphal	18/01.2023	ICM, Imphal	13.
Manipur	English	Imphal Times@MGL	Imphal	19/01/2023	Dr. N. Ranjana Devi, Sr. Consultant, NCCT	14.
Tamilnadu	Tamil	Dinakaran	Madurai	19/01/2023	ICM, Madurai	15.
Tamilnadu	Tamil	Malai Malar	Madurai	19/01/2023	ICM, Madurai	16.
Uttar Pradesh	Hindi	UPCM News	Uttar Pradesh	20/01/2023	IGICM Lucknow	17.
Uttar Pradesh	Hindi	UPCM News	Uttar Pradesh	20/01/2023	IGICM Lucknow	18.
Rajasthan	Hindi	Sahakar Srishti	Rajasthan	20/01/2023	Shri Mangal Jit Rai, Chairman, NCDFI	19.
Uttar Pradesh	Hindi	परिधि समाचार	बरेली	21/01/2023	IGICM Lucknow	20.
Assam	English	Assam Tribune	Assam	22/01/2023	ICM Guwahati	21.
Bihar	Hindi	Prabhat Khabar	Patna	23/01/2023	RICM Patna	22.
Maharashtra	Marathi	"Rashtra Sanchar"	Pune	23/01/2023	VAMNICOM Pune	23.

भारत

Posted at: Jan 9 2023 9:12PM

पैक्स के कंप्यूटरीकरण के नियम तय, कुल 2516 करोड़ रुपये के बजट से 63 हजार में पैक्स लगेंगे कम्प्यूटर

नयी दिल्ली, 09 जनवरी (वार्ता) देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की कार्यविधियों में सुधार ला कर उन्हें अपने व्यवसाय में विविधता लाने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण की आदर्श नियमावली राज्यों द्वारा स्वीकार कर ली गयी है और इसके साथ यह काम अब तेजी से शुरू करने की तैयारी है।

नेशनल कौंसिल फॉर कोआपरेटिव ट्रेनिंग (एनसीसीटी) के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "इससे पैक्स के काम में पारदर्शिता और दक्षता आएगी तथा इनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। पैक्स को पांचायत स्तर पर नोडल डिलीवरी सर्विस केंद्र बनने में मदद मिलेगी।" पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के मुख्य घटकों में डाटा स्टोरेज, क्लाउड आधारित एकीकृत कंप्यूटर साफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा ,हार्डवेयर, पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण और रख-रखाव की व्यवस्था शामिल हैं।

एनसीसीटी के सचिव मोहन मिश्रा ने यूनीवार्ता से कहा, "पैक्स कंप्यूटरीकरण के नियम निर्धारित हो चुके हैं। राज्यों ने केंद्र द्वारा इस संबंध में प्रतिपादित मॉडल नियमावली को स्वीकर कर लिया है। इससे अब यह काम गति पकड़ेगा।"

गौरतलब है कि गृह और सहकारिता मंत्री अमिति शाह की अगुवाई में सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत पैक्स कंप्यूटरीकरण के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रमंडल स्वीकृति पहले ही दे चुका था। तय नियमों के अनुसार इस परियोजना में साइबर सुरक्षा और डाटा भडांरण के साथ ईआरपी आधारित कॉमन सॉफ्टिेयर का विकास, वर्तमान अभिलेखों के डिजिटलीकरण , पैक्स को हाडावेयर संबंधी सहायता, अनरुक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण शामिल है।

नियमों के अनुसार यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा जिसमें राज्यों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। परियोजना प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू) केंद्र और राज्य स्तर पर स्थापित की जाएंगी। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी।

उन राज्यों के मामले में जहां पैक्स का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो गया है वहां उन्हें 50 हजार रुपये प्रति पैक्स की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए शर्त है कि इसके लिए उन्हें कॉमन सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ना होगा तथा उनका होर्डवेयर निर्देशों के अनुरूप हो और सॉफ्टवेयर पहली फरवरी 2017 के बाद चालू किया गया हो।

इस परियोजना में 2516 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ लगभग 63,000 क्रियाशील पैक्स का कंप्यूटरीकरण होना है जिसमें केंद्र सरकार 1528 करोड़ रुपये का योगदान करेगी।

श्री मिश्रा ने कहा कि इन समितियों में लगभग 13 करोड़ किसान सदस्य हैं। ये समितियां अर्थव्यवस्था के लिए हैं पर इनमें से ज्यादातर का हिसाब किताब हाथ से ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता में इसके ऊपर के दो स्तरों राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) को पहले ही नाबार्ड ने स्वचालित बना दिया है औ उन्हें साझा बैंकिंग साफ्टवेयर मंच पर लाया जा चुका है।

श्री मिश्रा ने कहा कि सहकारिता मंत्री पूरे पूरे सहकारी ऋण सुविधा तंत्र के कंप्यूटरीकरण के माध्यम से उसे राष्ट्रीय साझा मंच से जोड़ने के मंत्रालय के संकल्प को बार बार दोहरा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन सहकारी संस्थाओं के लिए एक सामान्य लेखा प्रणाली लागूकरने का भी प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा कि पैक्स का कम्प्यूटरीकरण से वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और खास कर छोटे और सीमांत किसानों के लिए सेवा वितरण प्रणाली को मजबतू करने में मदद मिलेगी और उन्हें उर्वरक, बीज आहद जैसी सामग्री के लिए नोडल सेवा वितरण बिंदु भी बन जाएगा। पैक्स ग्रामीण क्षेत्र में डिजटलीकरण में सुधार के साथ बकैंकांग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के वितरण केंद्र के रूप में भी मदद कर सकती हैं।

सरकार का मानना है कि सहकारी क्षेत्र के अनुसार इससे पैक्स के काम में पारदर्शिता आएगी और लगभग 13 करोड़ किसानों को इसको इसका लाभ होगा जिसमें अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं।

मनोहर, उप्रेती

Site : Univarta | 09/01/2023
Author : Manohar Uprti,

Link : http://www.univarta.com/rules-for-computerization-of-pacs-fixed-with-a-total-budget-of-rs-2516-crore-computers-will-be-installed-in-63-thousand-packs/India/news/2894100.html

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण

लखन लाल साहू
पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ, रायपुर

2516 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ 63, 000 कार्यात्मक पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।

लगभग 13 करोड़ किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं।

इससे पारदर्शिताए दक्षता आएगीए विश्वास बढ़ेगा और पैक्स को पंचायत स्तर पर नोडल डिलीवरी सर्विस पॉइंट बनने में मदद करेगा।

डेटा स्टोरेज के साथ क्लाउड आधारित एकीकृत सॉफ्टवेयरए साइबर सुरक्षाए हार्डवेयरए मौजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरणए रखरखाव और प्रशिक्षण मुख्य घटक हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैक्स की दक्षता बढ़ानेए उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लानेए पैक्स को उनके व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियों ध् सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ;पैक्सद्ध के कम्प्यूटरीकरण का निर्णय लिया है। यह परियोजना भारत सरकार के 1528 करोड़ रुपये के हिस्से के साथ 2516 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ लगभग 63ए000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव करती है।

सहकारिता का कृषि क्षेत्र में विस्तार

केन्द्रीय सहकारिता एवं गृहमंत्री अमित शाह कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र में सहकारिता को विशेष महत्व दे रह है। केन्द्र सरकार का सहकारिता मंत्रालय मिशन कोड में काम करने लगा है। दूध शक्कर खाद के बाद अब कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियाँ ;पैक्सद्ध देश में तीन.स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण ;ैज्ब्द्ध के सबसे निचले स्तर का गठन करती हैंए जिसमें लगभग 13 करोड़ किसान इसके सदस्य हैंए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य दो स्तरों अर्थात राज्य सहकारी बैंक एसटीसीबी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक डीसीसीबी को पहले ही नाबार्ड द्वारा स्वचालित बना दिया गया है और इसे कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर सीबीएस प्लैटफ़ार्म पर लाया गया है।

हालाँकि अधिकांश पैक्स अब तक कम्प्यूटरीकृत नहीं हुए हैं और अभी भी मैन्युअल रूप से कार्य कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इनमें अक्षमता और विश्वास की कमी व्याप्त है। कुछ राज्यों में पैक्स का स्टैंड अलोन और आंशिक कम्प्यूटरीकरण किया गया है। उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ़्टवेयर में एकरूपता नहीं है और वे डीसीसीबी और एसटीसीबी के साथ परस्पर जुड़े हुए नहीं हैं। श्री अमित शाहए माननीय गृह और सहकारिता मंत्री के कुशल मार्गदर्शन मेंए पूरे देश में सभी पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन प्लैटफ़ार्म पर लाने और उनके दिन दृ प्रतिदिन के कार्यों में एक सामान्य लेखा प्रणाली ;ब्ौद्ध लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

पैक्स का कम्प्यूटरीकरणए वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों ;ैडथ्द्ध को सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावाए विभिन्न सेवाओं और उर्वरकए बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिंदु भी बन जाएगा। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में सुधार के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ.साथ गैर.बैंकिंग गतिविधियों के आउटलेट के रूप में पैक्स की पहुंच में सुधार करने में मदद करेगी। डीसीसीबी तब विभिन्न सरकारी योजनाओं ;जहां क्रेडिट और सब्सिडी शामिल हैद्ध को हाथ में लेने के लिए महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक के रूप में स्वयं को नामांकित कर सकते हैंए जिन्हें पैक्स के माध्यम से लागू किया जा सकता है। यह राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ ऋणों का त्वरित निपटानए कम स्थानांतरण लागतए त्वरित लेखापरीक्षा और भुगतान तथा लेखांकन संबंधी असंतुलन में कमी सुनिश्चित करेगा।

इस परियोजना में साइबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के साथ ईआरपी आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर का विकासए पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करनाए अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मौजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा जिसमें राज्यों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन करना संभव होगा। परियोजना प्रबंधन इकाइयां ;पीएमयूद्ध केंद्र और राज्य स्तर पर स्थापित की जाएंगी। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी।

उन राज्यों के मामले में जहां पैक्स का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो गया हैए 50ए000ध्. रुपये प्रति पैक्स की प्रतिपूर्ति की जाएगीए बशर्ते वे कॉमन सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत ध् अपनाने के लिए सहमत होंए उनका हार्डवेयर आवश्यक विनिर्देशों को पूरा करता हो और सॉफ़्टवेयर 1 फ़रवरीए 2017 के बाद चालू किया गया हो।

दैनिक श्रमबिन्दु | 10/01/2023 | Page No. 4 Circulation: 17,183

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਪ.ਪ.) : ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੈਕਸ) ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਪਧਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ (ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਬੀਜ਼) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀਜ਼) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.) ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਕਸ ਅਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਕਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀ.ਏ.ਐਸ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। -ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ
RozanaSpokesman.com

Title : Computerization of PACS
Newspaper : Rozana Spokesman, Chandigarh | 12/01/2023 | Page No. 4 Circulation: 1,00,074

Home राष्ट्रीय प्रदेश खेल कोविड-19

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का होगा कंप्यूटरीकरण,13 करोड़ किसानों मिलेगा लाभ

POSTED BY Vineeta Haldar | PUBLISHED January 12, 2023 | 9:18 am | UPDATED | 10:55 am

० 2516 करोड़ रुपये खर्च होगा ,छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की दक्षता बढ़ाने, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने, उनके व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियों / सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उसका कम्प्यूटरीकरण का निर्णय लिया है। इस फैसले से 63,000 कार्यात्मक पैक्स का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। कम्प्यूटरीकरण पर 2516 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से 1528 करोड़ रुपये भारत सरकार मदद देगी। प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियाँ (पैक्स) देश में तीन-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण (STCC) के सबसे निचले स्तर का गठन करती हैं, जिसमें लगभग 13 करोड़ किसान सदस्य हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य दो स्तरों अर्थात राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) को पहले ही नाबार्ड द्वारा स्वचालित बना दिया गया है और इसे कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर (सीबीएस) प्लैटफ़ार्म पर लाया गया है।

हालाँकि, अधिकांश पैक्स अब तक कम्प्यूटरीकृत नहीं हुए हैं और अभी भी मैन्युअल रूप से कार्य कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इनमें अक्षमता और विश्वास की कमी व्याप्त है। कुछ राज्यों में पैक्स का स्टैंड अलोन और आंशिक कम्प्यूटरीकरण किया गया है। उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ़्टवेयर में एकरूपता नहीं है और वे डीसीसीबी और एसटीसीबी के साथ परस्पर जुड़े हुए नहीं हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, के कुशल मार्गदर्शन में, पूरे देश में सभी पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन प्लैटफ़ार्म पर लाने और उनके दिन – प्रतिदिन के कार्यों में एक सामान्य लेखा प्रणाली (CAS) लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

पैक्स का कम्प्यूटरीकरण, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (SMFs) को सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा, विभिन्न सेवाओं और उर्वरक, बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिंदु भी बन जाएगा। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में सुधार के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के आउटलेट के रूप में पैक्स की पहुंच में सुधार करने में मदद करेगी। डीसीसीबी तब विभिन्न सरकारी योजनाओं (जहां क्रेडिट और सब्सिडी शामिल है) को हाथ में लेने के लिए महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक के रूप में स्वयं को नामांकित कर सकते हैं, जिन्हें पैक्स के माध्यम से लागू किया जा सकता है। यह राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ ऋणों का त्वरित निपटान, कम स्थानांतरण लागत, त्वरित लेखापरीक्षा और भुगतान तथा लेखांकन संबंधी असंतुलन में कमी सुनिश्चित करेगा।

इस परियोजना में साइबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के साथ ईआरपी आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मौजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा जिसमें राज्यों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन करना संभव होगा। परियोजना प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू) केंद्र और राज्य स्तर पर स्थापित की जाएंगी। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन राज्यों के मामले में जहां पैक्स का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो गया है, 50,000 रुपये प्रति पैक्स की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते वे कॉमन सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत / अपनाने के लिए सहमत हों, उनका हार्डवेयर आवश्यक विनिर्देशों को पूरा करता हो और सॉफ़्टवेयर 1 फरवरी, 2017 के बाद चालू किया गया हो।

Site : Samvet Srijan
Ms. Vineeta Halder | 12/01/2023

Link : https://samvetsrijan.com/01/12/national/79342/

हार्दिक बधाई।

प्राथमिक कृषि साख समीतियों का हुआ कंप्यूटरीकरण

जासं, चंडीगढ़ : प्राथमिक कृषि साख समीतियां सबसे छोटी सहकारी ऋण संस्था और मूलभूत इकाई है। यह देश के त्रि-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण (एसटीसीसी) का सबसे निचला स्तर है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है और इसमें लगभग 13 करोड़ किसान इसके सदस्य हैं। देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों का 41 फीसद (3.01 करोड़ किसान) खाता है और पीएसीएस के माध्यम से इन केसीसी ऋणों (2.95 करोड़ किसानों) का 95 फीसद छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। अन्य दो स्तरों अर्थात। राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) को पहले ही नाबार्ड द्वारा स्वचालित कर दिया गया है और कामन बैंकिंग साफ्टवेयर (सीबीएस) पर लाया गया है।

यूटी खेल विभाग ने शहर के एकमात्र सेक्टर-16 स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूदा सुविधाओं को बेहतर करने का फैसला लिया है। खेल विभाग के प्रोपोजल पर यूटी इंजीनियरिंग विभाग इन दिनों काम कर रहा है। जानकारी अनुसार क्रिकेट स्टेडियम में जल्द ही प्रैक्टिस पिच (नेट पिच) की संख्या को बढ़ाने की तैयारी है। अगले दो महीने के भीतर खिलाड़ियों को पांच नई पिच मिल जाएगी।

इंजीनियरिंग विभाग क्रिकेट स्टेडियम में शांतिकुंज की तरफ चार टर्फ और एक सीमेंटेड पिच तैयार करेगा। क्रिकेट स्टेडियम में 150 से अधिक युवा और रणजी स्तर के क्रिकेटर के लिए सिर्फ 12 पिच हैं। बीसीसीआइ की ओर से यूटीसीए को मान्यता मिलने के बाद अब सेक्टर-16 क्रिकेट स्टेडियम में घरेलू और रणजी स्तर के काफी मैचों का आयोजन होने लगा है। मौजूदा सत्र में ही यूटीसीए को करीब 22 मैचों की मेजबानी मिली है। अधिकतर क्रिकेट मैच 16 क्रिकेट स्टेडियम में ही खेले जाते हैं। रणजी मैचों के आयोजन के समय प्रैक्टिस पिच रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले

दैनिक जागरण, चंडीगढ़

13/01/2023 | पेज न. 4 Circulation: 21,910

Punjabi Jagran (Chd)
13.01.2023 Pg no. 3

ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹਰਦੀਪ

ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਐੱਚਸੀ ਲਾਲੜੂ ਦੇ

ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੰਘ, ਰਿੰਪੀ ਬਾਲੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੰਜੀਵ
ਕੁਮਾਰ, ਸੀਮਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ

ਸਨ।

ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ

ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ
ਤੱਕ ਚੱਲੇਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਸੁਦਨ- ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ-ਰੀਜਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ - 32 ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ (ਐੱਸਟੀਸੀਸੀ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਟੀਸੀਬੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀਸੀਸੀਬੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (ਸੀਬੀਐੱਸ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਅਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਸੀਸੀਬੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀਸੀਬੀਐੱਸ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਏਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 63,000 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ 2516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਡਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨ ਲਈ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਉਡ ਅਧਾਰਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 2516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 63,000 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਐੱਸਐੱਮਐੱਫਐੱਸ) ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੌਡਲ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਵਜੋਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਡੀਸੀਸੀਬੀਐੱਸ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਘੱਟ ਤਬਾਦਲਾ ਲਾਗਤ, ਤੇਜ਼ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਈਆਰਪੀ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ (ਪੀਐੱਮਯੂਐੱਸ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਗਭਗ 200 ਪੈਕਸ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ,
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿ
ਅੰਦਰ 9 ਤੋਂ 1
ਚਲਾਉਣ ਅ
ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ
ਡਾ. ਜੰਗਜੀਤ ਸ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲ
ਲਈ ਇੱਕ ਵਿ
ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ
ਕੋਟਪਾ ਐਕਟ 2
ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬ
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤੰ
ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੇਵ
ਵਾਲ਼ੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀ
ਕੋਟਪਾ ਐਕਟ ਦੀ
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ,
ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿ
ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿ
ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦ
ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦੁਕਾਨ
ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵ

Title : Computerization of PACS

Newspaper : Punjabi Jagran, Chandigarh | 13/01/2023 | Page No. 3 Circulation: 24,708

Title : Computerization of PACS & Model Bye Laws of PACS
Newspaper : Punjabi Tribune | 16/01/2023
Circulation: 11,515

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ...

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

• ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਤੇ
ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਵੀ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਆਦਿ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1904 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 1912 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸਾਲ 1935 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 19164 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3953 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੋਲਟਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ (387) ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (305), ਸੰਗਰੂਰ (287), ਪਟਿਆਲਾ (282), ਜਲੰਧਰ (250), ਬਠਿੰਡਾ (202) ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ (202) 'ਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ (8), ਸੰਗਰੂਰ (8) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (7) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲਗਭਗ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਲਾਭ 'ਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ। ਇਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 10.93 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ (5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.62 (33 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ।

ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਥੋਕ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੰਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

मध्यमवर्गीय कृषि ऋण समीतियों का जल्द होगा कंप्यूटरीकरण

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन में सुधार और बैंकिंग गतिविधियों के साथ गैर बैंकिंग गतिविधियों में सुधार लाने के लिए छोटे एवं मध्यमवर्गीय कृषि ऋण समीतियों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा।

सरकार के इस आदेश से 13 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त होगा। इससे समाज का प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के प्रति विश्वास बढ़ेग। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना भारत के 63000 प्राथमिक कृषि सहकारी समीतियों के कंप्यूटरीकरण का प्रस्ताव करती है। सरकार इस दिशा में तेजी से बढ़ रही है, ताकि लोगों को सुगम और बेहतरीन सुविधाएं मिल सकें।

दैनिक जागरण, चंडीगढ़ |

17/01/2023 | पेज न. 4 Circulation: 21,910

হুইয়েন লানপাউ

HUEIYEN LANPAO

Vol. 46, Issue No. 287 | HUEIYEN LANPAO | Wednesday, January 18, 2023, Imphal | www.hueiyenlanpao.com | RNI No. 40746/1978 | ₹ 5.00

ইম্ফাল মনুংদা নুমিৎ ১৫নিগী মতুংদগী টৌটি ঈশিং ফংলরোই

হিরোইন ১সুং দব্রিয়ু ৱাই টেব্লেটকা কোন্নবা ফারবা কম্মান্দো ৫ কোর্টতা পুথোরকখ্রে

নুমিৎ ১১নিগী পুলিস কষ্টদি রিমান্দ লৌখ্রে

নেসনল লোক অদালট

উরিপোক এ সীদা মীরেপ ওইখিবা খোম্লোংময়ুম সুরেসকী অপুনবা লন-থুমগী শেনফম লুপা ১৬,৫১,৯৬,৬৩১ ওইখি

পোপি পাম্বীশিং লেপ্তুনা য়াম্থংলি, লৌশঙসু মৈ থাদোক্লি

নুপী ১দগী হিরোইন গ্রাম ২৭৮ ফারে

নেতাজি সুভাসচন্দ্র বোসকী ১২৬শুবা মপোক কুমওন চয়োলগী থৌরম পাঙথোকখ্রে

হায়দুনা চাওখত্তে, প্রিমিটিভ ওই হায়গদৌরিব্রা? কনাগুম্বা ত্রাইবেল হায়বসিগী ৱাহম্থোক খঙদবা মানবা লোন্দাদা ইবিরকপসু য়াওরি। মদুদি "মৈতৈ চীংদগী কুমলকখিবনি চীংগী ইচিল ইনাওশিং অসিগা অমত্তনি অদুনা মৈতৈসু ত্রাইবেল ওইফম থোকই"। চুম্মী, নীংশিংবা থোক্লবা মতমগী ৱারীনি, চাংমী-তম্মী মচিল মনাওনি হৌরকফম অমত্তনি তৌবতবু ত্রাইবেল হায়বসি ফুরুপ অদুগী জেনেটিক আইদেন্টিটি নত্তে, সোসল ষ্টেটসনি। খুদম ওইনা গ্রেদ থার্দ এমপ্লোয়ী অমনা মথং মথং প্রমোসন কারক্লুনা গ্রেদ ৱান ওফিসরগী থাক য়ৌরকপগুম্বনি। গ্রেদ ৱান ওইরিবৈগী সেলরি বোনসতু অদুম লৌগে হায়বদি য়াফম থোক্তে। চীংগী ইচিল ইনাও ফুরুপশিংগী মরক্তগী ঙসিদি ঐখোয়সু ত্রাইবেলগী থাক্তা লৈত্রে এস টি লিষ্টতগী দিসেদ্যুল তৌবীরো হায়বদা য়ারোইদবা কনাসু লৈতে অহোইনদুম তশেংনা জিওগ্রাফিকেল ইশোলেসন হায়বসি ষ্টেট ষ্টেটতুগী মেন সোসাইটি অদুদগী রিফরেন্স লৌগদবনি হায়বদি সেদ্যুল্ড ত্রাইব হায়বসি ষ্টেট বেসিসনি। মরম অদুনবু ষ্টেটনা জষ্টিফাইদ ওই হায়না রেকমেন্দেসন থাবীয়ু হায়না তক্লরিবনি। ষ্টেট অদুনা জষ্টিফাইদ ওই ওইদে লেপ্পা অদুনা ষ্টেট অদুগী লোজিকেল জষ্টিফিকেসন অদুনি।

হন্দক্তা অমুক নৌনা য়েলহৌমী অমা ওইনা মৈতৈবু অদিবাসি (ওরিজিনেল ইনহেবিটেন্ট ওফ ইন্দিয়া) গা মান্নন মৈতৈসু অদিবাসিনি হায়বা ঐখোয়গী ইরক্তগী য়াওরকপা অসিমক্তি য়াম্না লাইবক থীবনি। ইশানা ইশাবু শক তাকচবা ঙল্লক্তবা অসিমক্তি হিংনা হিংনা শিরবগা পাংখকনি। মমাঙথক্কী অহলশিংনা মৈতৈ অরিয়ানশিংগী চাদা নাওদানি হায়রম্বগী নিংদোন পোম্বা ফবাৎত্রিবৈঙ অদিবাসিগী ৱাফম অমুক পুশিল্লকপসিদি

নং ২৬তা ৱা
accepted v
not the Dr
whose des
(Jharkhan
of the Nilgi
the Adivas
and hills)
মোঙ্গোলোইদ

মণিপুর ষ্টেটতা প্রাইমরি এগ্রিকলচরেল ক্রেদিট সোসাইটিজ (পি এ সী এস) কম্প্যুটরাইজেসন

Shri Kh Rangamlian Aimol

Director (i/c), Institute of Cooperative Management, Imphal
(An Institute of National Council for Cooperative Training, New Delhi, Ministry of Cooperation, Govt of India)

ইকায়খুম্নজরিবা ইন্দিয়াগী প্রাইম মিনিষ্টরগী ভিজনরি লিদরশিপকী মখাদা প্রাইমরি এগ্রিকলচরেল ক্রেদিট সোসাইটিজ (পি এ সী এস) কম্প্যুটরাইজেসনগী থবক হেন্না ফগৎহন্নবা পান্দমদা থবক অসি ত্রান্সপরেন্সি অমদি একাউন্টেবিলিটি পুরক্লবা ব্যুজিনেসকীদমক লৈহন্দুনা অমদি তোঙান তোঙানবা এক্টিভিটি/ সর্ভিসশিং পায়খৎতুনা পি এ সী এস কান্নবা করিনো হায়বদু ফংহন্নবা পান্দম মখাদা প্রাইমরি এগ্রিকলচরেল ক্রেদিট সোসাইটিজ (পি এ সী এস) কম্প্যুটরাইজেসন তৌবগী থবক অসি গভর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়াগী মিনিষ্ট্রি ওফ কোওপরেসননা ৱারেপ ওইনা লৌরগা পায়খৎপা সেন্ত্রেলগী প্রোজেক্টনি।

প্রোজেক্টসিনা মণিপুরদা গভর্ণমেন্ট ওফ ইন্দিয়ানা লুপা ক্রোর ১৫২৮গী স্যের য়াওরগা অপুনবা লুপা ক্রোর ২৫১৬ বডজেট আউটলে ফংগনি। মসিগী প্রোজেক্টনা ৬৩,০০০ ফঙ্কসনেল পি এ সী এসপু কম্প্যুটরাইজেসন তৌগনি। মণিপুরগী ওইনা টায়র অনীগী মণিপুর ষ্টেট কোওপরেটিভ বেঙ্ক লিমিটেদ এপেক্স লেভেল অদুগা ভিলেজ লেভেলগী ওইনা পি এ সী এসনি। অপুনবা পি এ সী এসনা ২৫৫ (১৫১ গ্রাম পঞ্চায়ট লেভেল মল্টিপপরজ কোওপরেটিভ সোসাইটিজ প্রাইভেট লিমিটেদ) না ভেল্লি দিষ্ট্রিক্টতা অদুগা ১০৪ এল এ এম পি এস লিমিটেদনা হিল দিষ্ট্রিক্ট ওইগনি। (এদমিনিষ্ট্রেটিভ রিপোর্ট ২০২১-২২, দিপার্টমেন্ট ওফ কোওপরেটিভ, গভর্ণমেন্ট ওফ মণিপুরগী মতুংইন্না) থবক অসিদা ফাইনান্সিএল ইনক্লুজনগী মথক্তা মরু ওইনা স্মোল এন্দ মার্জিনেল ফার্মরগী ফাইনান্সিএল দরকার ওইবা হার, মরূ-মরাং, ফৌদিনচিংবা য়েম্থোকপগী প্রোভিজন য়াওরি।

মসিগী রিপোর্ট অসিনা পি এ সী এসশিংগী বেঙ্কিং এক্টিভিটিজ অমসুং নন বেঙ্কিং এক্টিভিটিস খুঙ্গং (ভিলেজ) দা হেন্না থুনা চাওখৎপা ওইগনি। মসিগী প্রোজেক্টকী মতম অসি চহী মঙা ওইগনি। ২০২২-২০২৩দগী ২০২৬-২০২৭ ওইরনি।

ADVANCED COACH

OUR POSITION HOLDERS IN

HSLC 2022 TOPPERS STUDENTS

2nd Post DHANAJIT | 9th Post. SWATI | 10th Post KHENILA | 11th Post NEVITA | 15th Post AVANTIK

11 TH Post NEVITA | 4TH Post ROBINSON | 6TH Post SHAH MINHAZ | 8th Post. ANJU | 9th Post. ANAND | 16th Post THOUNGAMBA SAMANANDA

SCIENCE | ARTS

STATE BOARD (REVISION) | FOUND

10am to 3.30pm | X(Morning) - 16th Jan | SEPARA

STATE LEVEL MOCK TEST 2023 for

Class XII	Subject	NO EXAM FEE	Class X	Subject
8th Feb (Wed)	Physics	BOSEM COHSEM EXAM ORIENT-	2nd March(Thu)	Maths
10th Feb (Fri)	Chemistry		4th March (Sat)	Science
12th Feb (Sun)	Maths		6th March (Mon)	English
14th Feb (Wed)	Biology		8th March (Wed)	S. Science

For details visit office of NAGAMAPAL LAMABAM LEI

HL-B/7956/21/12-22/01

Name of Newspaper: Hueiyen Lanpao
Date of Publication: 18-01-2023
Page No. 5
Title Name: Computerization of PACS in the State of Manipur
Author: Shri Khoichung Rangamlian, Director (i/c), ICM, Imphal

মণিপুরদা প্রাইমারি এগ্রিকলচরেল ক্রেদিট সোসাইটিজ (পেক্স) কম্প্যুটরাইজেসন তৌবা

– শ্রীকেঐচ রাঙ্গামলিয়ান আইমোল
দিরেক্টর (আই / সি) ইন্সটিট্যুট ওফ কো–ওপরেটিভ মেনেজমেন্ট, ইম্ফাল

ইন্দিয়াগী প্রাইম মিনিষ্টরগী অশানবা মীৎয়েংগা লোয়নবা লিদরশিপ মখাদা ইন্দিয়া লৈঙাক্কী মিনিষ্ট্রি ওফ কো–ওপরেসন্না প্রাইমারি এগ্রিকলচরেল ক্রেদিট সোসাইটি (পেক্স)শিং কম্প্যুটরাইজেসন তৌবগী থবক অসি সেন্ট্রেল্লি স্পোন্সর প্রোজেক্ট অমা ওইনা পায়খৎনবা ব্বারেপ লৌখি। মসি পেক্সশিংগী থবক থৌরমদা হেন্না খুমাং চাওশিনহন্নবা পান্দমদা চথরকপনি। অসিগুম্বা পেক্সশিংগী ওপরেসনশিংদা ট্রান্সপরেন্সি অমসুং একাউন্টেবিলিটি পুরকপা ঙমহনবগা লোয়ননা পেক্সনা তোঙান তোঙানবা মখলগী এক্টিভিটিশিং অমসুং সার্ভিসনচিংবা কয়াদা মপুং ফানা থবক পাঙথোকপা ঙমহন্নবা থৌরাং অসি পায়খৎলকপনি। সেন্টর লৈঙাক্কী অনৌবা প্রোজেক্ট অসিনা হৌজিক নিংথিনা থবক তৌদুনা লৈরিবা লৈবাক অসিগী পেক্স লিশিং ৬৩ রোম কম্প্যুটরাইজেসন তৌনবা পান্দম থম্মি। মসিগী অপুনবা বজেটকী শেনফম্মা লুপা ক্রোর ২৫১৬ নি। মসিদা ইন্দিয়া গভর্নমেন্টনা মণিপুরগী ওইনা লুপা ক্রোর ১৫২৮ সিয়ার তৌরি। মসিগী খ্বাইদগী মথক থংবা থাক্তা মণিপুর ষ্টেট কো–ওপরেটিভ বেঙ্ক লিমিটেদতা থাক অনী লৈগদবা কো–ওপরেটিভ ষ্ট্রকচর থম্না হৌখ্রে। গ্রাম পঞ্চায়েৎ লেভেল মল্টিপর্পজ কো–ওপরেটিভ সোসাইটিজ লিমিটেদ / লার্জ এরিয়া মল্টিপর্পজ কো–ওপরেটিভ সোসাইটিজ লিমিটেদ হায়বা অনি অসিনি।

হায়রিবা লেভেল অনি অসি খুঙ্গংগী থাক্তা লৈগদবনি। মণিপুরগী ওইনা পেক্স ২৫৫ লৈরি। মসিগী মনুংদা তম্পাক্কী দিষ্ট্রিক্টশিংদা গ্রাম পঞ্চায়েৎ লেভেল মল্টিপর্পজ কো–ওপরেটিভ সোসাইটিগী মশীংনা ১৫১ নি অদুগা লার্জ এরিয়া মল্টিপর্পজ কো–ওপরেটিভ সোসাইটি ১০৪ না চীংগী দিষ্ট্রিক্টশিংদা লৈরি। হায়রিবা অসি ষ্টেট লৈঙক্কী দিপার্টমেন্ট ওফ কো–ওপরেসন্না ফোঙদোকখিবা এন্যুয়েল এদমিনিষ্ট্রেটিভ রিপোর্ট ২০২১–২২ গী মতুং ইন্ননি। হায়রিবা রেকোর্দ অসি মমাঙ চহী ২০২২ গী মার্চ ৩১ ফাওবগীনি। পেক্স কম্প্যুটরাইজেসন তৌবা অসিনা লায়রবা অমদি লম লৈজদবা লৌমীশিংদা ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজনগী খুদোং চাবা ফংহনবা অমদি সার্ভিস দেলিভরিগী থবক থৌরমদা সাধরন মীয়ামদা হেন্না ফিভম ফগৎহনবগী মথক্তা মসিনা তোঙান তোঙানবা সার্ভিস অমসুং প্রোভিজন কয়ামরুম মীয়ামদা ফংহন্নবা নোদেল সার্ভিস দেলিভরি পোইন্ট অমা ওইনসু মথৌ পাঙথোক্কনি। মীয়ামদা মতম মতমগী মরু–মরাং, মহৈ–মরোং অমদি হারনচিংবা পীবদসু হেন্না খুদোং চাহল্লগনি। সেন্ট্রেল্লি স্পোন্সর প্রোজেক্ট অমা ওইনা পেক্স কম্প্যুটরাইজেসন তৌবা অসিনা বেঙ্ককা মরী লৈনবা থবক থৌরমশিংদা পেক্সনা য়ৌশিন্দুনা মীয়ামগী হিংবগী থাকসু ব্রাংখৎহনগনি। খুঙ্গংগী লমশিংদা দিজিটেলাইজেসনগী থাক ব্রাখৎহনবগী মথক্তা নন–বেঙ্কিং এক্টিভিটিশিংদসু হেন্না কান্নবা পীরগনি।

- প্রোজেক্ট অসিনা ই আর পিদা য়ুম্ফম ওইবা, সাইবর সেক্যুরিটি অমসুং দাটা ষ্টোর তৌদুনা থম্বগী খুদোং চাবশিং য়াওরবা কম্মন সোফ্টৱয়ার দিভলপ তৌবা, পেক্সতা হার্টৱয়ারগী সপোর্ট পীবা, মেন্টেনেন্স সপোর্ট অমসুং ট্রেনিং য়াওনা হান্নদগী লৈজরক্লিবা রেকোর্দশিংসু দিজিটাইজ তৌবা ঙমহল্লগনি। সোফ্টৱয়ার অসি ভর্নাকুলর লেঙ্গুয়েজদা ষ্টোর তৌগদবনি। তোঙান তোঙানবা ষ্টেটশিংদা মথৌ তাগদবা অদু য়েংলগা কষ্টমাইজেসনগী থবকসু ওম্বোক ওনশিন তৌবা য়াহন্নবা থৌরাং অসি পায়খৎপনি। অনৌবা প্রোজেক্ট অসিগী মতম চহী ৫ ওইগনি। শেনবা চহী ২০২২–২০২৩ দগী ২০২৬–২০২৭ ফাওবা প্রোজেক্ট অসি চথগদবনি। মীয়াম্না মখা তাবা ঈ–পাউশীদ্মক লম্ফেলপাৎতা লৈরিবা আই সি এম, ইম্ফালগী দিরেক্টরদা কন্টেক্ট তৌরকপা য়াগনি।

Name of Newspaper: : Ichel Express
Date: 18-01-2023
Page No.6
Title: Computerization of PACS in the State of Manipur
Author: Shri Khoichung Rangamlian, Director (i/c), ICM, Imphal

The Tamenglong Times
DAILY NEWSPAPER Ningting hei pumtan ne Bi Lingual Formerly called Chamchiu
18 January 2023 (Wednesday) RNI-MANBIL/2019/77145 Published at Tamenglong Dist. HQs. Manipur Rs.4:00 Vol. 06, Issue 13 PAGE 1

Institute of Cooperative Management, Imphal

Computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in the state of Manipur

By: Shri Kh Rangamlian Aimol
Director (i/c), Institute of Cooperative Management, Imphal (An Institute of National Council for Cooperative Training, New Delhi, Ministry of Cooperation, Govt of India)

Centrally Sponsored Project for Computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) has taken a decision by the Ministry of Cooperation, Govt. of India under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister of India with the objective of increasing efficiency of PACS, bringing transparency and accountability in their operations; facilitating PACS to diversify their business and undertake multiple activities/ services. This project proposes computerization of about 63,000 functional PACS with a total budget outlay of Rs. 2516 Cr with Government of India share of Rs. 1528 Cr.

In Manipur, two tier cooperative structures are in place with The Manipur State Cooperative Bank Ltd. at the apex level and PACS i.e., Gram Panchayat Level Multipurpose Cooperative Societies Ltd/ Large Area Multipurpose Cooperative Societies Ltd at village level.

There are 255 nos PACS in the State (151 Gram Panchayat Level Multipurpose Cooperative Societies in the valley districts and 104 LAMPS in the hill districts) as on 31st March, 2022 (as per Annual Administrative Report 2021 -22, Dept of Cooperation, Govt. of Manipur).

Computerization of PACS, besides serving the purpose of financial inclusion and strengthening service delivery to farmers especially Small & Marginal Farmers (SMFs) will also will become nodal service delivery point for various services and provision of inputs like fertilizers, seeds etc. The project will help in improving the outreach of the PACS as outlets for banking activities as well as non-Banking activities apart from improving digitalization in rural areas.

The project will comprises of development of ERP based common software with cyber security and data storage, providing hardware support to the PACS, digitization of existing records including maintenance support and training. The software will be in vernacular language having flexibility of customization as per the needs of the States. Duration of the project will be for five years i.e., from 2022 – 2023 to 2026 – 2027. For further details please contact Director, ICM Imphal, Lamphelpat. □

Name of Newpaper: The Tamenglong Times
Date of Publication:18-01-2023
Page No 4

रैस्टवे एक्सप्रैस

Gen. Manager: Kulwant Singh Pala (Mob.: 9988440234) Chief Editor: Deepak Marwaha

वर्ष : 3 Email: news@restwayexpress.com G.M.: 9988440234 Restway Restway RESTWAY NEWS RNI No. PUNBIL/2017/72143

बहुराज्यीय विभिन्न सहकारी समितियों के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

होशियारपुर (रैस्टवे एक्सप्रैस) 18 जनवरी 2023 : (आनंद) क्षेत्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, चण्डीगढ़ के निदेषक श्री राज कुमार षर्मानेआज यहां पत्रकारों से भेट वार्ता दौरान बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारिता अधिनियम 2002 के नियम के तहत एक बहु–राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की मंजूरी दे दी है, जिसे भारतीय सहकारी बीज समिति लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की मल्टीस्टेट एक्सपोर्ट सोसाइटी की स्थापना, जैविक खेती, कृषि ऋण समितियों का कम्पयूटरीकरण, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के मॉडल उपनियम की जानकारी आदि समितियों की स्थापना की गई ।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2022 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की मल्टीस्टेट एक्सपोर्ट सोसाइटी की स्थापना की स्थापना और प्रचार को मंजूरी दी गई है । प्रांसांगिक मंत्रालयों, विषेष रूप से विदेष मंत्रालय और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से उनकी निर्यात संबंधी नीतियों, योजनाओं के माध्यम से समर्थन के साथ मंजूरी दी है । यह प्रस्तावित सोसायटी संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से सहकारी समितियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न निर्यात संबंधी योजनाओं और नीतियों का लाभ प्राप्त करने में भी मदद करेगी । यह सहकारी समितियों के समावेषी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार स`समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा । सहकारी सेवाओं को बढ़ाने से अतिरिक्त रोजगार भी पैदा होंगे । सहकारी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि बदले में "मे कई इंडिया" को भी बढ़ावा देगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा ।

सरकार के नये नियमों के अनुसार पैक्स के किये गये कम्पयूटरीकरण के अन्तर्गत लगभग 13 करोड़ किसानों को लाभ की प्राप्ति होगी ।

माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में पैक्स की डिजीटलाईजेषन सेकृषि भारत की अर्थव्यवस्था का और भी सुधार कर पायेंगे । यह परियोजना भारत के 63,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्पयूटरीकरण का प्रस्ताव करती है । आधुनिक समय में भी अधिकांष पैक्स मैनुअल रूप से कार्य कर रहीहैं । सभी राज्यों के पैक्स के सॉफ्टवेयर में एकरूप तालाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है ।

पैक्स के मॉडल उपनियमों की जानकारी उनके संबंधित उपनियमों द्वारा प्रतिबंधित है, जो ज्यादातर मामलों में दषकों पुरानी है और उनको संषोधन की आवष्यकता है । पैक्स का कृषि ऋण क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से ध्यान रखतें हैं । बाजार की मॉग के अनुसार मॉडल उपनियमों को जारी करना अनिवार्य प्रतीत होता है । इस मुददे को हल करने के लिए और ग्रामीण स्तर पर पैक्स को जीवंत आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न सहकारी संस्थाओं में से एक कमेटी का चयन किया गया ।

मंत्रिमंडल ने बहु उद्देषीय राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत एक बहु–राज्य सहकारी जैविक सोसायटी की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जोकि जैविक उत्पाद के लिए एक षीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी । बढ़ते स्वास्थ्य और पर्यावरण चेतना के कारण जैविक उत्पादों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाषकों के उपयोग के बिना कृषि उपज का उत्पादन किया जाता है । दुनिया भर में जैविक उत्पाद कों की सबसे बड़ी संख्या होने के बावजूद कुल 34 लाख में से 16 लाख जैविक उत्पादों के बाजार में भारत का योगदान केवल 2.7 प्रतिषत है । परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं, अपर्याप्त रसद अवसंरचना, बिखरा हुआ और खंडित उत्पादक आधार, ज्ञान भंडार की कमी, भारतीय बाजार की धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है । चौथी सबसे बड़ी जैविक जोत होने के बावजूद ये मद्देभारत को पिछड़ा बना रहे हैं ।

सहकारिता के समावेष विकास मॉडल काउपयोग करके यह " सहकार से समृद्धि" के उद्देष्य की प्राप्ति मेंसहकारी सदस्यों को अपनी जैविक वस्तुओं के लिए उच्च कीमतों का एहसास होने और समुदाय द्वारा उत्पादित अधिषेष से लाभांष प्राप्त करने से लाभ होगा ।

स्वदेषी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी और राष्ट्रीय स्तर की बहु–राज्यीय बीज सहकारी समिति उच्च गुणवता वाले बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण के लिए केंद्रीय संगठन के रूप में काम करेगी ।

बीजों की सालाना आवष्यकता 787 लाख क्विंटल है, इनमे से केवल 372 लाख क्विंटल की आपूर्ति संगठित क्षेत्र द्वारा की जाती है । बाकी 415 लाख क्विंटल असंगठित क्षेत्र म `हैं, जोकि खुद किसानों से आयतित है । भारत में रूपये 40,000 करोड़ के बीज बाजार में बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र का दबदबा है जहा किसानों का बड़े पैमाने पर षोषण होता है ।

Title: बहुराज्यीय विभिन्न सहकारी समितियों के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

Name of Newspaper: रैस्टवे एक्स्प्रेस

Date of Publication: 18.01.2023
Page No. 2
Author: Shri RK Sharma, Director RICM Chandigarh
Circulation: 8000

Regd. No. RNI 2009/28292 Email : thuhiltu@yahoo.com +91- 8837085827

NISÎN THUHILTU

(An Independent Bi-lingual Daily Newspaper)

US State Secretary Antony Blinken in 5-6 February, 2023 leh Russia in Ukraine a simna, China's nuclear arsenal leh China ah US mi hentang ah umte chungchang agenda tawh China pha ding, Chinese Foreign Minister Qin Gang tawh Beijing ah kimutua ding uh ti ahi.

Premier League match 6 lam ah gualzo lo ah a um ziak un Liverpool manager Jurgen Klopp in demna tuak maleh a panmun nusia ding ah hiatsak ahi masia Liverpool nusialo ding hi'n a gen hi. Klopp ahileh 2022 a khah 2026 tiang a ding ah contract suksaube ahi.

MANIPUR STATE AH PRIMARY AGRICULTURAL CREDIT SOCIETIES (PACS) COMPUTERIZATION

Primary Agricultural Credit Societies (PACS) sukhat zawk semna ding ah Prime Minister Narendra Modi mapuina ah Cabinet Committee on Economic Affairs in 29 June, 2022 ah Primary Agricultural Credit Societies (PACS) computerized bawl ding ah approved a bawl dungzui in, Manipur ah **Computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) project** chiapi ahi zing hi. Zia computerize thiltuppipen chu India gamsung ah PACS zosia computerize bawl ding leh nisin ah a business bawlnau a National level ah common platform khat neisak ding, Common Accounting System (CAS) umsak ding ti ahi. Zialo a chu central leh state levels ah Project Management Units (PMUs) umsak ding ti ahi.

Primary Agricultural Credit Society (PACS) ahileh India ah basic unit leh co-operative credit institutions neupen ah kihia, grassroots level (gram panchayat leh village level) ah farmer, abiktak ah Small & Marginal Farmers (SMFs)-te tawh rural economy siamhoina ding ah panla ahi. India gam sung ah kisan credit card (KCC) loans piak ah um 41% (3.01 crore farmers) te chu PACS apat a hiu a, zia ah 95% KCC loans (2.95 crore farmers) piak ah umte chu Small & Marginal Farmers (SMFs) te a hiu.

Three-tier Short-Term Cooperative Credit (STCC) ah Primary Agricultural Cooperative credit societies (PACS) in a nuainungpen hina a lua a, approx.13 Cr. Farmers te chu a member a hiu. Tier dang panite chu - State Cooperative Banks (StCBs) leh District Central Cooperative Banks (DCCBs) ahiu.

PACS computerization project chu total budget outlay Rs. 2516 crore (GoI share Rs. 1528 crore) tawh kum 5 (i.e., 2022 – 2023 - 2026 – 2027) sung ah functional PACS 63,000-te computerized bawl ding ti ahi. PACS tamzawte ahiuleh computerized hilo in, manual ah function a hi ziak un muan-ngamna a taksap bak a, hatzo taktak theilo ti ahi dungzui in computerization project chiapi a um a hi.

Manipur ah two-tier cooperative structures - Manipur State Cooperative Bank Ltd. (apex level) leh PACS i.e., Gram Panchayat Level Multipurpose Cooperative Societies Ltd/Large Area Multipurpose Cooperative Societies Ltd (village level) ah chiapi in a um hi. Manipur ah Annual Administrative Report 2021 -22, Dept of Cooperation, Govt. of Manipur dung in, 31st March, 2022 tiang a khah PACS 255 (valley district ah Gram Panchayat Level Multipurpose Cooperative Societies 151 leh hill districts ah Large Area Multipurpose Societies (LAMPS) 104) a um hi. Manipur ah registered cooperatives 12396 a um a, membership 688062 ahi.

Computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) project chu financial inclusion leh service delivery lam sukhatna ding mai hilo a, service chuamchuam - Direct Benefit Transfer (DBT), Interest Subvention Scheme (ISS), Crop Insurance Scheme (PMFBY) chiapina leh inputs lam ah fertilizers, seeds hawpdawna ah PACS chu Nodal Service Delivery Point khat hithei ding, PACS outreach siamhoitu hiding, rural areas ah digitalization suhat chuam ding ti le ahi. Zia project dungzui cloud based common software siamdaw ding, cyber security leh data storage kituptak tawh PACS te hardware support piak ding, records umsate digitize bawl ding ti ahi. Zia cloud based common software chu local mite pau (vernacular language) ah siamdaw ding, State te'n a mamaw dan zil ua software chu siam ding ti le a hi. Zia chungchang ah thuchian kimzaw Director, Institute of Cooperative Management (ICM), Imphal, Lamphelpat thudawt thei ding ahi.

India ah Primary Agricultural Credit Societies (PACS) 95,000 tuam a um a, zia te chu NABARD in District Central Cooperative Banks (DCCBs) 352 leh State Cooperative Banks (StCBs) 34-te mangcha'n refinanced bawl in, 13.12 crore farmers te chu PACS members a hiu.

Hiatthei khat chu, *Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002 mai ah National Level Multi-State Cooperative Seed Society; National Level Multi-State Cooperative Export Society leh National Level Multi-State Cooperative Organic Society* a um hi.

NATIONAL LEVEL MULTI-STATE SEED COOPERATIVE SOCIETY

National Level Multi-State Seed Cooperative Society ahileh production, procurement, processing,branding, labelling, packaging, storage, marketing lam leh thaichimu hawpdawna lam; research & development; system neitakah thaichietkawlna lam leh indigenous thaichi te masawnna ding ah panlakna apex organization ahi. Primary societies, district, state leh national level federations banah multi state cooperative societies te chu a member hithei a hiu.

NATIONAL LEVEL MULTI-STATE COOPERATIVE EXPORT SOCIETY

National Level Multi-State Cooperative Export Society ahileh export lam thil ah policies, schemes, agencies tawh kisai mawpua, procurement, storage, processing, marketing, branding, labelling, packaging, certification, research leh development etc chiapi ahi. Cooperatives 4 viz. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED), Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited (GCMMF) leh National Cooperative Development Corporation (NCDC) te'n ₹100 Crore chiat puadawk in, promoter members in a pang ui. National Level Multi-State Cooperative Export Society in umbrella organization khat hina tawh gamsung cooperative sector ah nasem thilbawl in, export lam a global markets in Indian cooperatives te masawnna ding in panlakna a nei hi.

NATIONAL LEVEL MULTI-STATE COOPERA ORGANIC SOCIETY:

National Level Multi-State Cooperative Organic Society ahileh Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Food Processing Industries, Ministry of Health & Family Welfare leh Ministry of Development of North Eastern Region tawh kithua ah panla, umbrella organization khat, organic products lam thil, a biktak ah aggregation, certification, testing, procurement, storage, processing, branding, labelling, packaging, logistic facilities, organic products marketing lam ah institutional support bawl leh organic farmer-te ding ah member cooperatives-te mangcha ah financial assistance arrange bawlpiak ahi. A member ah primary agricultural credit societies, district, state & national level federations, multi-state co-operative societies leh Farmers Producer Organisations (FPOs) te pangthei a hiu.

~ Kh Rangamlian Aimol
Director (i/c), Institute of Cooperative Management, Imphal
(An Institute of National Council for Cooperative Training, New Delhi, Ministry of Cooperation, Govt of India)

~ Seiminthang Khongsai
Faculty Member, Institute of Cooperative Management, Imphal
(An Institute of National Council for Cooperative Training, New Delhi, Ministry of Cooperation, Govt of India

Name of Newspaper: NISIN Thuhiltu
Date of Publication: 18.01.2023
Page No. 2
Author: Kh Rangamlian Aimol, Director &
Mr. Seiminthang Khongsai, Faculty Member, ICM Imphal

Empowering Cooperatives through Historic Reforms & Modernisation Computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS)

By: Dr. N. Ranjana Devi

The Union Cabinet's decision under the visionary leadership of the Prime Minister of India for Computerization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) can be considered as very supportive and optimistic action to increase efficiency of PACS, bringing transparency and accountability in their operations; facilitating PACS to diversify their business and undertake multiple activities/ services. This project proposes computerization of about 63,000 functional PACS throughout the country with a total budget outlay of Rs. 2516 Cr with Government of India share of Rs. 1528 Cr. The focus points are:

- *63,000 functional PACS will be computerized with overall budget outlay of Rs 2516 Crores*
- *Will benefit approx. 13 Crores farmers most of which are Small & Marginal Farmers*
- *Will bring transparency, efficiency, enhance trustworthiness and help PACS to become nodal delivery service point at Panchayat level*
- *Cloud based unified software with data storage, Cyber security, Hardware, digitization of existing records, Maintenance and Training are the main components*

The Primary Agricultural Cooperative credit societies (PACS) constitute the lowest tier of the three-tier Short-term cooperative credit (STCC) in the country comprising of approx.13 Cr. farmers as its members, which is crucial for the development of the rural economy. The other two tiers viz. State Cooperative Banks (StCBs) and District Central Cooperative Banks (DCCBs) have already been automated by the NABARD and brought on Common Banking Software (CBS).

However, majority of PACS have so far been not computerized and still functioning manually resulting in inefficiency and trust deficit. In some of the states, stand-alone and partial computerization of PACS has been done. There is no uniformity in the software being used by them and they are not inter-connected with the DCCBs and StCBs. Under the guidance of Shri Amit Shah, Minister of Home and Cooperation, it has been proposed to computerize all the PACS throughout the Country and bring them on a common platform at National level and have a Common Accounting System (CAS) for their day-to-day business.

Computerization of PACS, besides serving the purpose of financial inclusion and strengthening service delivery to farmers especially Small & Marginal Farmers (SMFs) will also will become nodal service delivery point for various services and provision of inputs like fertilizers, seeds etc. The project will help in improving the outreach of the PACS as outlets for banking activities as well as non-Banking activities apart from improving digitalisation in rural areas. The DCCBs can then enroll themselves as one of the important options for taking up various government schemes (where credit and subsidy is involved) which can be implemented through PACS. It will ensure speedy disposal of loans, lower transition cost, faster audit and reduction in imbalances in payments and accounting with State Cooperative Banks and District Central Cooperative Banks.

The project comprises of development of ERP based common software with cyber security and data storage, providing hardware support to the PACS, digitization of existing records including maintenance support and training. This software will be in vernacular language having flexibility of customization as per the needs of the States. Project Management Units (PMUs) will be set up at Central and State levels. District Level support will also be provided at cluster of about 200 PACS. In the case of states where computerization of PACS has been completed, Rs. 50,000/- per PACS will be reimbursed provided they agree to integrate with/ adopt the common software and their hardware meets the required specifications, and the software was commissioned after 1st February, 2017.

The present scenario in Manipur

Total no. of Cooperative Societies registered : 12396

Total membership : 688062

No. of Primary Agricultural Cooperatives : 271 (114534 members)

Out of 271 Primary Agricultural Credit Societies (PACS), 151 are Gram Panchayat Level Multi Purpose cooperative Societies in the Valley, 104 Large Area Multipurpose Societies in the Hilly Region and 16 Service Cooperative Societies. Majority of the Cooperatives are not in good health in the State and as a result they are not in a position to provide the credit and other services. A cooperative is an autonomous association of persons units voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. They are based on the value of Self-Help, self responsibility, democracy, equality and solidarity. Cooperative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others. All over the world cooperatives follows a set of seven principles viz; voluntary and open membership, democratic member control, member economic participation, autonomy and independence, education, training and information, cooperation amongst cooperatives and concern for community. The cooperative model allows people with limited capital to come together and work on a large scale.

Inspite of their long existence after registration, the cooperatives have not been able to push forward due to many reasons such as lack of member participation, inadequate fund, unprofessional management, inefficient leadership, lack of awareness about the cooperative benefits etc.

Now, the good news is that after the formation of a separate Ministry of Cooperation by the Government of India under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and Cooperation Minister Shri Amit Shah, the Cooperative Vehicle is moving ahead with various schemes for the benefits of cooperative members at the grassroot level. The formulation of new National Cooperative Policy will take place very soon. The preparation of Model-bye-laws for PACS has already been completed by the Ministry of Cooperation, Govt. of India which is followed by recent cabinet approvals for setting up of a National Level Multi State Cooperative Seed Society, Multi State Cooperative Organic Society and National Level Multi State Cooperative Export Society under Multi State Cooperative societies Act 2002. It is a wake-up call for all cooperatives and all concerned

(The author is a Senior Consultant, NCCT, New Delhi)

Name of Newspaper: Imphal Times@MGL
Date of Publication: 19.01.2023 Page No. 2
Author: Dr. N Ranjana Devi

தொடக்க மேலாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் கணினி மயம்

மதுரை, ஜன. 19: தொடக்க மேலாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் முழுமையான கணினிமயமாக்கம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நாட்டின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. பருவகால விவசாய நடவடிக்கைகளை சங்கங்களின் உறுப்பினர்கள் உரிய காலத்தில் மேற்கொள்வதற்கு பயிர்க்கடன்கள் மற்றும் விவசாய இடுபொருட்கள் வழங்குவதன் மூலம் விவசாய வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதில் இச்சங்கங்கள் உறுதுணை புரிகின்றன. தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூன்று அடுக்கு நிர்வாக அமைப்பின் கீழ் செயல்பட்டு வருகின்றன.

இதன் படி மாநில அளவில் மாநில கூட்டுறவு வங்கிகள், மாவட்ட அளவில் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் கிராமிய அளவில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் பணியாற்றுகின்றன. இதில் சுமார் 13 கோடி விவசாயிகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். இது கிராமப்புற பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானது. மற்ற இரண்டு அடுக்குகள் அதாவது மாநில கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகள் ஏற்கனவே நபார்டு வங்கி மூலம் தானியங்கி வசதியில், பொது வங்கி மென்பொருள் இயக்கத்தில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், பெரும்பாலான சங்கங்கள் இதுவரை முழுமையான முறையில் கணினிமயமாக்கப்படவில்லை. இதனால் தற்கால சூழ்நிலைக்கேற்ற வாறு வேகமான, துல்லியமான, திறமையான, நம்பிக்கையான மற்றும் வெளிப்படையான உறுப்பினர் சேவைகள் புரிவதில் நடைமுறைச்சிக்கல் ஏற்படுகிறது. இந்நிலையில், மத்தியக்கூட்டுறவு அமைச்சகம் அகில இந்திய அளவில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களின் செயல்திறனை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடனும் அவற்றின் செயல்பாடுகளில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வை கொண்டுவரும் நோக்கத்துடனும் இக்கடன் சங்கங்களை முழுமையாக கணினிமயமாக்கும் திட்டத்தினை சமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது. அதிகாரிகள் கூறும்போது, "சங்கங்கள் கணினித் தளத்தில் இயங்குவதற்கும் மற்றும் பொதுக் கணக்கியல் முறையை முழுவீச்சில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் ஏதுவாக அமையும். இந்தத் திட்டமானது தற்போது செயல்பாட்டிலுள்ள அனைத்து சங்கங்களையும் கணினிமயமாக்க முன்மொழிகிறது. இதன் மொத்த பட்ஜெட் ரூ.2,516 கோடி. இதில் இந்திய அரசின் பங்கு ரூ.1,528 கோடியாகும்" என்றனர்.

Title : Computerisation of Primary Agricultural Cooperative Credit Society

News Paper - Dinakaran, Tamilnadu | 19/01/2023 | Page No. 3 Circulation: 4,55,873

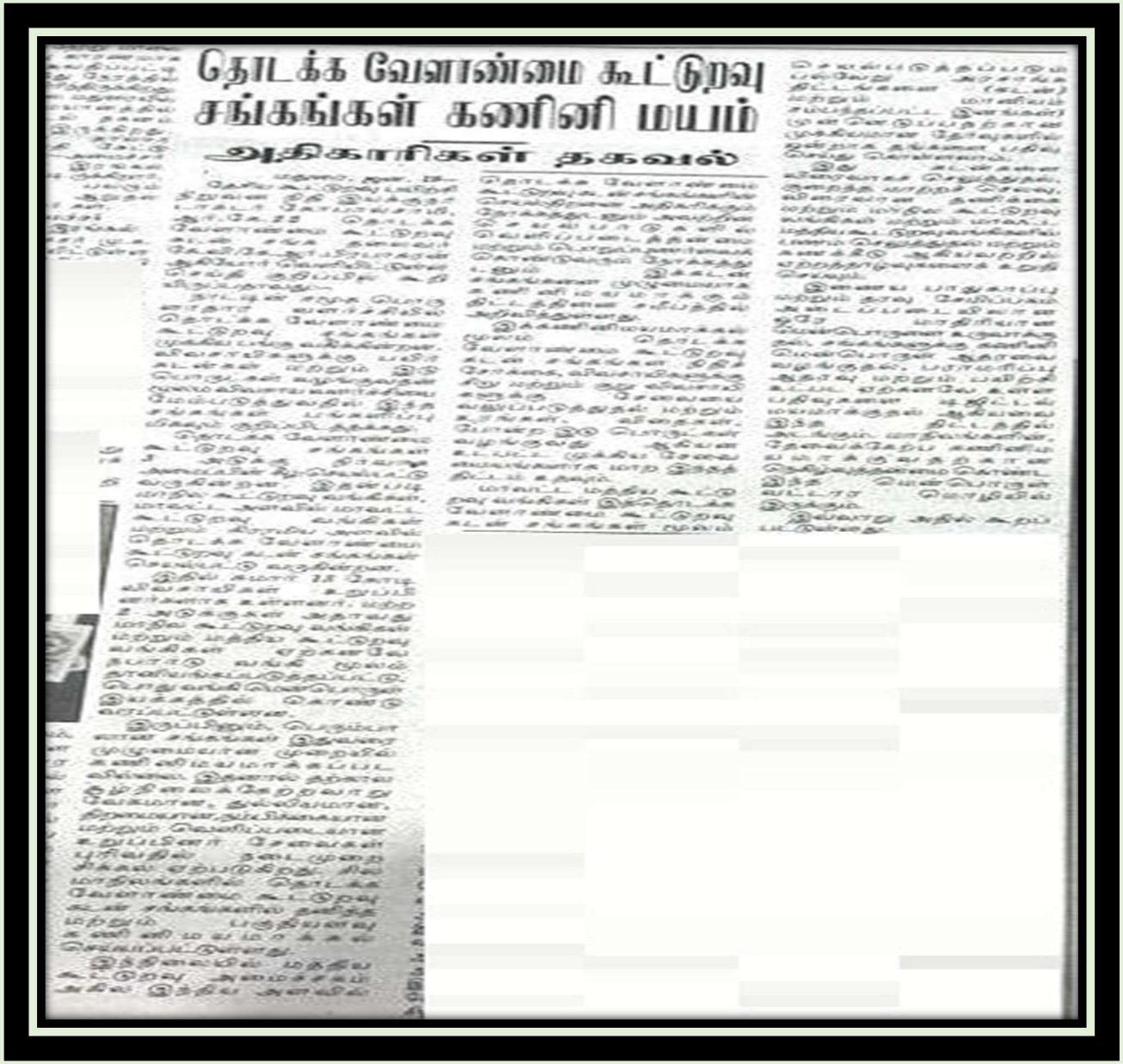

தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள் கணினி மயம்

அதிகாரிகள் தகவல்

Title : Computerisation of Primary Agricultural Cooperative Credit Society

News Paper – Malai Malar, Tamilnadu | 19/01/2023

बहुराज्यीय सहकारी समिति सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

UPCM News January 20, 2023

इंदिरा गाँधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ के निदेशक, डॉ0 एस0 एन0 झा ने बताया कि देश के तीव्र आर्थिक विकास की अभिकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए देश के अर्थशास्त्रियों ने देश के जनमानस की समृद्धि हेतु सहकारिता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने की अनुसंशा की है। इन अनुसंशाओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अपनी पहली कैबिनेट बैठक में तीन बहुराज्यीय सहकारी समिति एक्ट को मूर्तरूप देने का कार्य किया। ये तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियां बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति, बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति एवं बहुराज्यीय सहकारी जैविक समिति हैं ।

इन समितियों के गठन के पश्चात् एक तरफ जहाँ हमारे निर्यात को प्रोत्साहन होगा तो दूसरी तरफ कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज भी उपलबध हो पाएगें एवं खेती पर निर्भर किसानों की आय में भी वृद्धि हो पाएगी । इन समितियों से देश के आर्थिक विकास में सहकारिता एक सशक्त भूमिका का निर्वहन करेगी। इससे जुड़े सदस्यों की आर्थिक भागीदारी उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी एवं देश के पांच ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था प्राप्ति के सपने को साकार करने में भी अपना वांछित सहयोग प्रदान कर पाएगी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त देश में कुल 95 हजार पैक्स में से 63 हजार प्रभावी पैक्स को 2516 करोड़ रूपये के बजट से कम्प्यूटरीकृत किया जाना भी प्रस्तावित है। जिससे लगभग 13 करोड़ सीमांत एवं छोटे किसानों को लाभ प्राप्त होगा एवं पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता भी हासिल हो पाएगी । पैक्स का कम्प्यूटरीकरण वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा विभिन्न सेवाओं और उर्वरक बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिन्दु भी बन जाएगा।

परियोजना से साइबर सुरक्षा और डेटा भण्डारण के साथ ईआरपी आधारित सॉफ्टवेर का विकास, पैक्स को हार्डवेअर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मैजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेर स्थानीय भाषा में होगा। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी । आशा है कि सहकारी संस्थाएं राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक, विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी ।

Title : बहुराज्यीय सहकारी समिति सहकार से समृद्धि की ओर एक सराहनीय कदम

News Paper – UPCM News – New Agency | 20/01/2023 |

प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण तकनीक द्वारा कुशल प्रबंधन की पहल

UPCM News January 20, 2023

इंदिरा गाँधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ के निदेशक (प्र0) डॉ0 एस0 एन0 झा ने बताया कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) की दक्षता बढ़ाने, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने, पैक्स को उनके व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियों / सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण का निर्णय लिया है। इस योजना द्वारा 63,000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है । जिसके लिए कुल रू0 2516 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है ।

वर्तमान में अधिकांश पैक्स कम्प्यूटरीकृत नहीं हुए हैं और अभी भी मैन्युअल रूप से कार्य कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इनमें अक्षमता और विश्वास की कमी व्याप्त है। कुछ राज्यों में पैक्स का स्टैंड अलोन और आंशिक कम्प्यूटरीकरण किया गया है। उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ़्टवेयर में एकरूपता नहीं है और वे डीसीसीबी और एससीबी के साथ परस्पर जुड़े हुए नहीं हैं। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में, पूरे देश में सभी पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन प्लेटफ़ार्म पर लाने और उनके दिन – प्रतिदिन के कार्यों में एक सामान्य लेखा प्रणाली (CAS) लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

पैक्स का कम्प्यूटरीकरण, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा, विभिन्न सेवाओं और उर्वरक, बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण केंद्र भी बन जाएगा। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में सुधार के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के आउटलेट के रूप में पैक्स की पहुंच में सुधार करने में मदद करेगी।

इस परियोजना में साइबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के साथ ईआरपी आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मौजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा जिससे राज्यों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन करना संभव होगा। परियोजना प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू) केंद्र और राज्य स्तर पर स्थापित की जाएंगी। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन राज्यों के मामले में जहां पैक्स का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो गया है, 50,000/- रुपये प्रति पैक्स की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते वे कॉमन सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत / अपनाने के लिए सहमत हों, उनका हार्डवेयर आवश्यक विनिर्देशों को पूरा करता हो और सॉफ़्टवेयर 1 फरवरी, 2017 के बाद चालू किया गया हो। ऐसा करने के उपरांत उन सभी समितियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर कुशल प्रबंधन की ओर एक कदम उठाया जा सकेगा।

Title : प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण तकनीक द्वारा कुशल प्रबंधन की पहल

News Paper – UPCM News – New Agency | 20/01/2023 |

देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्राथमिक कृषि ऋण में सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान

मंगल जित राई
अध्यक्ष-भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ (एनसीडीएफआई) अध्यक्ष-सहकार भारती सिक्किम प्रदेश

प्राथमिक कृषि ऋण समिति (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी), भारत में सबसे मूलभूत और सबसे छोटी सहकारी ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। यह सबसे निचले स्तर (ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्तर पर) पर कार्य करती है। भारत में लगभग एक लाख प्राथमिक ऋण समितियां है जिसमें अकेले महाराष्ट्र में इक्कीस हजार से अधिक समितियां है।

जून 2022 में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की दक्षता बढ़ाने तथा उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने व विभिन्न गतिविधियां/सेवाएं शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में कुल 2516 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय होगा, जिसमें केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 1529 करोड़ रुपये की होगी। पांच वर्षों की अवधि में लगभग 63,000 कार्यरत पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है। इससे करीब 19 करोड़ किसानों को लाभ होगा।ध्यातव्य है कि लघु और सीमांत किसानों को ऋण देने में इन समितियों की भूमिका लगभग 50 फीसदी है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया।

सहकारिता मंत्रालय का गठन हो या उसके बाद इस क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में लिए गये सभी निर्णय, यह बताते है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का 'सहकार से समृद्धि' मात्र एक वाक्य नहीं है बल्कि सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मोदी जी का अटूट संकल्प है।

नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज लगभग 63,000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो सहकारिता क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है और उनका कंप्यूटरीकरण इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा।

* मैं इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।

* करीब 2516 करोड़ रुपये की लागत से 63000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा जिससे करीब 13 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे।

* इस डिजिटल युग में पैक्स के कंप्यूटरीकरण से उनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए मंत्रिमंडल द्वारा आज लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है।

अमित शाह ने अपने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा कि सहकारिता मंत्रालय का गठन हो या उसके बाद इस क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में लिए गये सभी निर्णय, यह बताते है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का 'सहकार से समृद्धि' मात्र एक वाक्य नहीं है बल्कि सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मोदी जी का अटूट संकल्प है। इसी कड़ी में आज मोदी कैबिनेट ने लगभग 63000 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पैक्स सहकारिता क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है और इसका कंप्यूटरीकरण इस क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा। मैं इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2,516 करोड़ रुपये की लागत से से 63000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा जिससे लगभग 13 करोड़ छोटे व सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। इस डिजिटल युग में पैक्स के कंप्यूटरीकरण के निर्णय से उनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता व कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और यह बहुउद्देशीय पैक्स को लेखांकन की सुविधा भी प्रदान करेगा।

अमित शाह ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। साथ ही इससे पैक्स को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस),फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) आदि विभिन्न सेवाएं प्रदान करने और खाद, बीज आदि इनपुट प्रदान करने के लिए एक नोडल सेंटर बनने में भी मदद मिलेगी।

पैक्स के मॉडल उपनियमों पर संक्षिप्त जानकारी

देश में लगभग 95,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) स्थित हैं, जिन्हें नाबार्ड द्वारा 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबीएस) और 34 राज्य सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। इन पैक्स में 13.12 करोड़ किसान सदस्य है। पैक्स किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि का ऋण प्रदान करके देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि अकेले इन व्यवसायों से होने वाली आय, पैक्स की संचालन गतिविधियों को जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में, पैक्स द्वारा जाने वाली आर्थिक गतिविधियां उनके संबंधित उपनियमों द्वारा प्रतिबंधित है, जो ज्यादातर मामलों में दशकों पुरानी है और उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है।

इस मुद्दे को हल करने के लिए और ग्रामीण स्तर पर पैक्स को जीवंत आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए, नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंकों, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमनीकॉम), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए प्रारूप मॉडल उपनियम तैयार करने के लिए किया गया था। इन्हें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार मंत्रालयों, राष्ट्रीय सहकारी समितियों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों को उनकी टिप्पणियां/प्रतिक्रिया के लिए दिनांक 1.7.2022 को परिचालित किया गया था। इस पर आम जनता के सुझाव भी मांगे गए थे। संबंधित सभी हितधारकों से 1500 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें मॉडल उपनियमों के मसौदे में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया था।

ये मॉडल उपनियम पैक्स को 25 से अधिक क्षेत्रों (कृषि और गैर-कृषि, ऋण और गैर-ऋण) में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम बनाएंगे, इस प्रकार उन्हें बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (बहु-उद्देशीय पैक्स) में परिवर्तित कर देंगे।मॉडल उपनियमों के अनुसार पैक्स द्वारा की जा सकने वाली कुछ सांकेतिक व्यावसायिक गतिविधियां इस प्रकार है- अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण, उर्वरक और कीटनाशक वितरण, बीज वितरण, मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गी पालन गतिविधियां, कृषि मशीनरी, कृषि उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मछली/झींगा खेती, चिकन, भेड़, बकरी, सुअर पालन, रेशम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न की खरीद, सोर्टिंग, ग्रेडिंग, सफाई गतिविधियां, पैकेजिंग से संबंधित गतिविधियां, कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, भंडारण सुविधा (वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज), सामुदायिक केंद्र, अस्पताल, शिक्षा, उचित मूल्य की दुकानें, एलपीजी-पेट्रोल-डीजल डीलरशिप, बैंक मित्र/ व्यावसायिक पत्राचार, बीमा सुविधा, कामन सर्विस सेंटर / डेटा सेंटर, लॉकर सुविधा आदि, यह देश में कृषि के व्यापक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।

मॉडल उपनियमों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं और कानूनी तथा प्रशासनिक संरचना, पैक्स के संचालन के क्षेत्र के विस्तार से संबंधित आवश्यक प्रावधान शामिल है जो इस प्रकार है- ऋण पोर्टफोलियो में विविधीकरण, लम्बी अवधि के ऋण का प्रावधान, व्यापार से संबंधित सेवाओं में विस्तार, सदस्यता संबंधी प्रावधान, निदेशक मंडल (बीओडी), सामान्य निकाय और प्रबंधन संबंधी प्रावधान, लेखापरीक्षा आदि को शामिल किया गया है।ये पैक्स को एक सक्षम कानूनी और प्रशासनिक ढांचा प्रदान करेंगे ताकि उनके लिए बेहतर शासन व्यवहार्य व्यवसाय संचालन और कुशल कार्य पद्धति उपलब्ध हो सके। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहु सेवा केंद्र और एकल खिड़की एजेंसियों के रूप में कार्य किया जा सके।

मॉडल उपनियमों को पैक्स परियोजना के कम्प्यूटरीकरण के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके तहत मॉडल उपनियमों में उल्लिखित सभी व्यावसायिक गतिविधियों को शामिल करते हुए एक एकल ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।पैक्स को समर्थन प्रदान करने के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्राम सभा / सरकारी भूमि उपलब्ध कराने, उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) के लिए लाइसेंस और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्न की खरीद के लिए पैक्स को एजेंसी के रूप में नामित करने आदि के संबंध में माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र पहले ही भेजा जा चुका है।

ये मॉडल उपनियम केवल सांकेतिक प्रकृति के है और संबंधित पैक्स अपने संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुसार उपयुक्त संशोधनों के बाद उन्हें अपना सकते है।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण

* 2516 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ 63,000कार्यात्मक पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा।

* लगभग 13 करोड़ किसानों को इसका लाभ प्राप्त होगा जिसमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान है।

* इससे पारदर्शिता, दक्षता आएगी, विश्वास बढ़ेगा और पैक्स को पंचायत स्तर पर नोडल डिलीवरी सर्विस पाइंट बनने में मदद करेगा।

* डेटा स्टोरेज के साथ क्लाउड आधारित एकीकृत सॉफ्टवेयर,साइबर सुरक्षा, हार्डवेयर, मौजूदा रिकार्ड का डीजिटलिकरण, रखरखाव और प्रशिक्षण मुख्य घटक है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शिता पूर्ण नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैक्स की दक्षता बढ़ाने, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने, पैक्स को उनके व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियों/सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण का निर्णय लिया है। यह परियोजना भारत सरकार के 1528 करोड़ रुपये के हिस्से के साथ 2516 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ लगभग 63000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव करती है।

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियाँ (पैक्स) देश में तीन-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण (एसटीसीसी) के सबसे निचले स्तर का गठन करती हैं, जिसमें लगभग 13 करोड़ किसान इसके सदस्य हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य दो स्तरों अर्थात राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) को पहले ही नाबार्ड द्वारा स्वचालित बना दिया गया है और इसे कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर (सीबीएस) प्लेटफार्म पर लाया गया है।

हालांकि अधिकांश पैक्स अब तक कम्प्यूटरीकृत नहीं हुए है और अभी भी मैन्युअल रूप से कार्य कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इनमें अक्षमता और विश्वास की कमी व्याप्त है। कुछ राज्यों में पैक्स का स्टैंड अलोन और आंशिक कम्प्यूटरीकरण किया गया है।उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर में एकरूपता नहीं है और वे डीसीसीबी और एसटीसीबी के साथ परस्पर जुड़े हुए नहीं है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में, पूरे देश में सभी पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन प्लेटफार्म पर लाने और उनके दिन-प्रतिदिन के कार्यों में एक सामान्य लेखा प्रणाली (सीएएस) लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। पैक्स का कम्प्यूटरीकरण, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा, विभिन्न सेवाओं और उर्वरक,बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण बिंदु भी बन जाएगा। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में सुधार के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के आउटलेट के रूप में पैक्स की पहुंच में सुधार करने में मदद करेगी। डीसीसीबी तब विभिन्न सरकारी योजनाओं (जहां क्रेडिट और सब्सिडी शामिल है) को हाथ में लेने के लिए महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक के रूप में स्वयंको नामांकित कर सकते है,जिन्हें पैक्स के माध्यम से लागू किया जा सकता है। यह राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ ऋणों का त्वरित निपटान,कम स्थानांतरण लागत,त्वरित लेखापरीक्षा और भुगतान तथा लेखांकन संबंधी असंतुलन में कमी सुनिश्चित करेगा। इस परियोजना में साईबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के साथ ईआरपी आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मौजूदा रिकार्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा जिसमें राज्यों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन करना संभव होगा। परियोजना प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू) केंद्र और राज्य स्तर पर स्थापित की जाएंगी। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन राज्यों के मामले में जहां पैक्स का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो गया है, 50,000/ रुपये प्रति पैक्स की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते वे कॉमन सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत/अपनाने के लिए सहमत हो, उनका हार्डवेयर आवश्यक विनिर्देशों को पूरा करता हो और सॉफ्टवेयर 1 फरवरी 2017 के बाद चालू किया गया हो।

निष्कर्ष :- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिरसे जीवित करने के लिए पैक्स प्रणाली को बदलने की तत्काल आवश्यकता है। पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दक्षता प्राप्त करने के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) नाबार्ड द्वारा के कम्प्यूटरीकरण इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Title: देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्राथमिक कृषि ऋण में सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान

Newspaper: Sahakar Srishthi | 20 /01/2023 | Page No. 4 Circulation: 2700

प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का किया जाएगा कंप्यूटरीकरण

तकनीक द्वारा कुशल प्रबंधन की पहल

परिधि समाचार ब्यूरो, पीलीभीत इंदिरा गाँधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ के निदेशक (प्र0) डॉ0 एस0 एन0 झा ने बताया कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) की दक्षता बढ़ाने, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने, पैक्स को उनके व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियों / सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण का निर्णय लिया है। इस योजना द्वारा 63,000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है। जिसके लिए कुल रू0 2516 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में अधिकांश पैक्स कम्प्यूटरीकृत नहीं हुए हैं और अभी भी मैन्युअल रूप से कार्य कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इनमें अक्षमता और विश्वास की कमी व्याप्त है। कुछ राज्यों में पैक्स का स्टैंड अलोन और आंशिक कम्प्यूटरीकरण किया गया है। उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ़्टवेयर में एकरूपता नहीं है और वे डीसीसीबी और एससीबी के साथ परस्पर जुड़े हुए नहीं हैं। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में, पूरे देश में सभी पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन प्लैटफ़ार्म पर लाने और उनके दिन दृ प्रतिदिन के कार्यों में एक सामान्य लेखा प्रणाली (ҽ) लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। पैक्स का कम्प्यूटरीकरण, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने और विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा, विभिन्न सेवाओं और उर्वरक, बीज आदि जैसे इनपुट के प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण केंद्र भी बन जाएगा। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में सुधार के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के आउटलेट के रूप में पैक्स की पहुंच में सुधार करने में मदद करेगी। इस परियोजना में साइबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के साथ ईआरपी आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर का विकास, पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना, अनुरक्षण संबंधी सहयोग और प्रशिक्षण सहित मौजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल है। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में होगा जिससे राज्यों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन करना संभव होगा। परियोजना प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू) केंद्र और राज्य स्तर पर स्थापित की जाएंगी। लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन राज्यों के मामले में जहां पैक्स का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो गया है, 50,000/- रुपये प्रति पैक्स की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते वे कॉमन सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत / अपनाने के लिए सहमत हों, उनका हार्डवेयर आवश्यक विनिर्देशों को पूरा करता हो और सॉफ़्टवेयर 1 फरवरी, 2017 के बाद चालू किया गया हो। ऐसा करने के उपरांत उन सभी समितियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर कुशल प्रबंधन की ओर एक कदम उठाया जा सकेगा।

Title: प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का किया जाएगा कंप्यूटरीकरण
Newspaper: परिधि समाचार | 21 /01/2023 | Circulation: 2000

SATURDAY, JANUARY 21, 2023

PACS computerisation

Employees to be given training on handling software

STAFF REPORTER

GUWAHATI, Jan 20: The Institute of Cooperative Management (ICM), Guwahati will provide necessary training to the employees on handling software in connection with the computerisation of Primary Agricultural Cooperative Credit Societies (PACS) in the State.

HK Das, director (incharge) of ICM, Guwahati, said computerisation of PACS would bring transparency, efficiency, enhance trustworthiness and help PACS become the nodal delivery service point at the panchayat level.

"The employees will be taught how to keep records and maintenance of accounts with the help of the software. Computerisation will be done in two phases. In Assam, out of the total 806 Gaon Panchayat Samabai Samitis (GPSS), 586 will be computerised in the first phase," Das said.

"Computerisation of PACS, besides serving the purpose of financial inclusion and strengthening service delivery to farmers, especially small and marginal farmers (SMFs), will also become a nodal service delivery point for various services and provision of inputs like fertilizer, seeds, etc. This will help improve the outreach of the PACS as outlets for banking activities as well as non-banking activities, apart from improving digitalisation in rural areas," he added.

"The project comprises the development of cloud-based common software with cyber security and data storage, providing hardware support to the PACS and digitalisation of existing records, including maintenance support and training. This software will be in vernacular language having the flexibility of customisation as per the needs of the states," he further said.

ASSAM ELECTRICITY GRID CORPORATION LIMI

Title: PACS computerisation
Newspaper: Assam Tribune | 22 /01/2023 | Circulation: 46,775

प्रभात खबर

पटना, सोमवार
23.01.2023

07

सहकारिता. ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की जरूरतें होंगी पूरी

2500 पैक्स का कंप्यूटरीकरण एक मंच पर मिलेंगी 25 सुविधाएं

संवाददाता,पटना

ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को बहुसेवा केंद्र और एकल खिड़की एजेंसियों के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया जा रहा है. 25 सेवाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराने और तकनीक द्वारा उनका कुशल प्रबंधन की पहल के तहत बिहार में पहले चरण में 2,500 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) का कंप्यूटरीकरण किया जायेगा. लगभग 200 पैक्स के समूह में जिला स्तर पर सहायता भी प्रदान की जायेगी. पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा होने पर 50 हजार रुपये प्रति पैक्स की प्रतिपूर्ति की जायेगी.पैक्स तीन स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा (एसटीसीसी) के सबसे निचले स्तर पर है. यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है. राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) को पहले ही नाबार्ड ने स्वचालित बना दिया है. पैक्स भी कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर (सीबीएस) प्लेटफॉर्म पर होंगी. रोजाना के कार्यों में एक सामान्य लेखा प्रणाली लागू की जायेगी. डीएनएस क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान के निदेशक डॉ केपी रंजन बताते हैं कि पैक्स के मैन्युअल होने से इनमें अक्षमता और विश्वास की कमी है. यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण में सुधार के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के आउटलेट के रूप में पैक्स की पहुंच में सुधार करने में मदद करेगी.

छोटे और सीमांत किसानों की सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा विभिन्न सेवा,उर्वरक, बीज जैसे इनपुट प्रावधान के लिए नोडल सेवा वितरण केंद्र बनेगा

पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा होने पर 50 हजार रुपये प्रति पैक्स की प्रतिपूर्ति की जायेगी

एक ही प्लेटफॉर्म से इन सुविधाओं को दिलाने में होगी मदद

अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण, उर्वरक और कीटनाशक वितरण, बीज वितरण, मत्स्य पालन, डेयरी, मुर्गी पालन गतिविधियां, कृषि मशीनरी, कृषि उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मछली – झींगा खेती, चिकन, भेड़, बकरी, सुअर पालन, रेशम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न की खरीद, संग्रह, ग्रेडिंग, सफाई – पैकेजिंग से संबंधित गतिविधियां, कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, भंडारण सुविधा (वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज), सामुदायिक केंद्र, अस्पताल, शिक्षा, उचित मूल्य की दूकाने, पेट्रो पदार्थो की डीलरशिप, बैंक मित्र, व्यावसायिक पत्राचार, बीमा सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर – डेटा सेंटर लॉकर सुविधा आदि.

पैक्स किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि का ऋण प्रदान करके देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते है. अकेले इन व्यवसायों से होने वाली आय पैक्स की संचालन गतिविधियों को जारी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है. वर्तमान में पैक्स द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों उनके संबंधित उपनियमों द्वारा प्रतिबंधित है, जो ज्यादातर मामलों में दशकों पुरानी हैं और उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता है.

डॉ केपी रंजन, निदेशक , डीएनएस क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान , पटना

Title: 2500 पैक्स का कंप्यूटरीकरण एक मंच पर मिलेगी 25 सुविधाएं
Newspaper: प्रभात खबर | 23 /01/2023 | पृष्ठ 7

राष्ट्रसंचार 23-1-2023 पा.नं. 4

पारदर्शकता, उत्तरदायित्वासह विकासाच्या दिशेने वाटचाल

प्राथमिक कृषी पतसंस्था होणार सक्षम

प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (PACS) ही देशातील तीन-स्तरीय अल्प-मुदतीच्या सहकारी पतसंस्थेची (STCC) सर्वात खालची पातळी आहे. ज्यात सुमारे रु. १३ कोटी आहे.

लक्षवेधी
जगदीश आदित्य दिनकर
संशोधन अधिकारी, वैमनी कॉम, पुणे

- ६३,००० कार्यात्मक PACS 2516 कोटी रुपयांच्या एकूण बजेट परिव्ययासह संगणकीकृत केले जातील.
- अंदाजे फायदा होईल १३ कोटी शेतकरी यापैकी बहुतेक लहान आणि सीमांत शेतकरी आहेत.
- पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणेल, विश्वासार्हता वाढवेल आणि PACS ला पंचायत स्तरावर नोडल वितरण सेवा बिंदू बनण्यास मदत करेल.
- डेटा स्टोरेजसह क्लाउड आधारित युनिफाइड सॉफ्टवेअर, सायबर सुरक्षा, हार्डवेअर, विद्यमान रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन, देखभाल आणि प्रशिक्षण हे मुख्य घटक आहेत.

भारताच्या माननीय पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने PACS ची कार्यक्षमता वाढवणे, त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याच्या उद्देशाने प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) चे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. PACS ला त्यांच्या व्यवसायात विविधता आणण्यासाठी आणि अनेक उपक्रम,सेवा सुरू करण्यासाठी सुविधा देणे. हा प्रकल्प सुमारे ६३,००० फंक्शनल PACS चे संगणकीकरण प्रस्तावित करतो आणि एकूण बजेट खर्च रु. २५१६ कोटी भारत सरकारच्या हिस्सासह रु. १५२८ कोटी आहे.

प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (PACS) ही देशातील तीन-स्तरीय अल्प-मुदतीच्या सहकारी पतसंस्थेची (STCC) सर्वात खालची पातळी आहे. ज्यात सुमारे रु. १३ कोटी आहे. शेतकरी त्याचे सदस्य आहेत, जे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. इतर दोन स्तर उदा. राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) नाबार्डने आधीच स्वयंचलित केल्या आहेत आणि कॉमन बँकिंग सॉफ्टवेअर (CBS) वर आणल्या आहेत.

तथापि, बहुतेक PACS आतापर्यंत संगणकीकृत केलेले नाहीत आणि तरीही ते मॅन्युअली कार्य करत आहेत परिणामी अकार्यक्षमता आणि विश्वासाची कमतरता आहे. काही राज्यांमध्ये PACS चे स्वतंत्र आणि आंशिक संगणकीकरण करण्यात आले आहे. त्यांच्याद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये एकसमानता नाही आणि ते DCCBs आणि StCBs शी एकमेकांशी जोडलेले नाहीत. माननीय गृह आणि सहकार मंत्री श्री. अमित शहा यांच्या समर्थ मार्गदर्शनाखाली, देशभरातील सर्व PACS चे संगणकीकरण करून त्यांना राष्ट्रीयस्तरावर एका सामायिक व्यासपीठावर आणण्याचा आणि त्यांच्यासाठी कॉमन अकाउंटिंग सिस्टीम (CAS) तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. ते दैनंदिन व्यवसायात उपयुक्त ठरेल.

PACS चे संगणकीकरण, आर्थिक समावेशन आणि शेतकऱ्यांना विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना (SMFs) सेवा वितरण बळकट करण्याच्या उद्देशाने विविध सेवांसाठी नोडल सर्व्हिस डिलिव्हरी पॉइंट बनतील आणि खते, बियाणे इ. सारख्या निविष्ठांची तरतूद करेल. प्रकल्प मदत करेल. ग्रामीण भागात डिजिटलायझेशन सुधारण्याव्यतिरिक्त बँकिंग क्रियाकलापांसाठी तसेच नॉन-बँकिंग क्रियाकल्पांसाठी आउटलेट म्हणून PACS च्या पोहोचामध्ये सुधारणा करणे आहे.

DCCB नंतर विविध सरकारी योजना (जेथे क्रेडिट आणि सबसिडी समाविष्ट आहे) हाती घेण्यासाठी एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून नावनोंदणी करू शकतात. ज्या PACS द्वारे लागू केल्या जाऊ शकतात. हे कर्जाची जलद विल्हेवाट, कमी संक्रमण खर्च, जलद ऑडिट आणि राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील पेमेंट आणि अकाउंटिंगमधील असमतोल कमी करणे सुनिश्चित करेल.

सायबर सुरक्षा आणि डेटा स्टोरेजसह ERP आधारित कॉमन सॉफ्टवेअरचा विकास, PACS ला हार्डवेअर सहाय्य प्रदान करणे, देखभाल समर्थन आणि प्रशिक्षणासह विद्यमान रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन यांचा या प्रकल्पात समावेश आहे. हे सॉफ्टवेअर राज्यांच्या गरजेनुसार सानुकूलित करण्याची लवचिकता असलेले स्थानिक भाषेत असेल.

केंद्र आणि राज्य स्तरावर प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट्स (पीएमयू) स्थापन केले जातील. सुमारे २०० PACS च्या क्लस्टरमध्ये जिल्हा स्तरावरील सहाय्य देखील प्रदान केले जाईल.

पीएसीएसचे संगणकीकरण पूर्ण झालेल्या राज्यांच्या बाबतीत रु.५०,०००/- प्रति PACS ची परतफेड केली जाईल जर ते सामान्य सॉफ्टवेअरसह एकत्रित,अवलंबण्यास सहमत असतील, त्यांचे हार्डवेअर आवश्यक वैशिष्ट्यांची पूर्तता करुन कार्यान्वित केले जाईल.

Title: PACS Computerisation
Newspaper: "Rashtra Sanchar" dated 23.1.23 at page No.4.
Published by Shri Jagdish Aaditya Dinkar, Research Officer, VAMNICOM Pune

एनसीसीटी की प्रशिक्षण इकाइयां

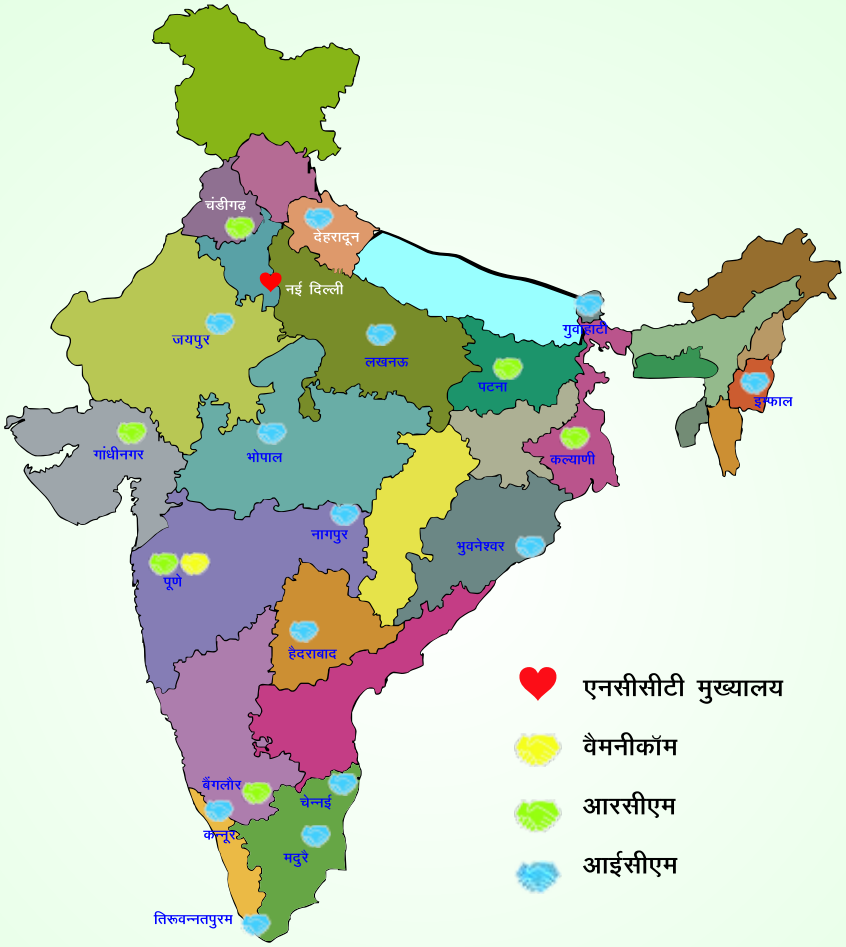

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमोटेड एक स्वायत्त संस्था)

3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, तीसरा तल, एनसीयूआईई बिल्डिंग, नई दिल्ली –110016

011-41096510 secy-ncct@gov.in www.ncct.ac.in